

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून दिनांक- जनवरी, 2009

विषय : नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2006-08 में स्वीकृत कार्यों की धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 684/V-श0वि-06-206(सा0)/05 टी0सी0-। दिनांक 25-3-2006 के क्रम में शासनादेश संख्या 59/IV-श0वि-06-206(सा0)/05 टी0सी0-। दिनांक 12-3-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए रु० 605.81 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त कुल रु० 460.19 लाख स्वीकृत किया गया। उक्त के अनुक्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 1633/एन0पी0/1-लेखा/2008-09 दिनांक 3-1-2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त अब स्वीकृति हेतु अग्रशेष धनराशि रु० 145.62 लाख में से रु. 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि रु. 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तों पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
- 2- शासनादेश संख्या 684/V-श0वि-06-206(सा0)/05 टी0सी0-। दिनांक 25-3-2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- 4- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रोत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
- 5- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगमन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने तथा अवमुक्त जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग व कार्य में न्यूनतम दर का विवरण देते हुए ही देय समस्त अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का प्रस्ताव किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- स्वीकृत कार्यों की न्यूनतम स्वीकृत निदिदाओं के सापेक्ष हुई बचतों का विवरण उपलब्ध कराये जाने तथा पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि के उपयोग के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
- 2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सि0- 1119/XXVII(2)/2009, दिनांक- 21 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं०- 70
(1)/IV-शा0वि0-08, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, कूमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 6- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
- 10- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।
- 11- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड बुक।

अज्ञा से,
(विजय कुमार ढौडियाल)
अपर सचिव।